दैनिक सामयिकी: ०२.०६.२०२१

बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) शुरू किया।

प्रमुख बिंदु

क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) के बारे में:

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB)** द्वारा कार्यान्वित, एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम CDP का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पहचाने गए बागवानी समूहों को बढ़ाना और विकसित करना है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने **53 बागवानी क्लस्टर की पहचान की है, जिनमें से 12 को कार्यक्रम के पायलट लॉन्च के लिए चुना गया है।**
- CDP से लगभग 10 लाख किसानों और मूल्य श्रृंखला के संबंधित हितधारकों को लाभ होगा।
- सभी 53 क्लस्टर में लागू होने पर CDP से 10,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

भारत में बागवानी क्षेत्र:

- भारत विश्व स्तर पर बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया के सब्जियों और फलों के उत्पादन का लगभग 12% है।
- भारत केला, आम, अनार, एसिड लाइम, आंवला और सपोटा जैसे फलों के उत्पादन में अग्रणी है।

हाल ही में उठाए गए कदम:

- मंत्रालय ने **'MIDH-मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर'** के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 2250 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ आवंटन प्रदान किया है।
- MIDH बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

'PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COVID19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए **'PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन'** योजना की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- COVID19 के कारण माता-पिता दोनों या माता-पिता में से जीवित बचे या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को 'PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत सहायता दी जाएगी।

'PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के बारे में:

- ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर मासिक वित्तीय सहायता और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर PM केयर्स से 10 लाख रुपये की राशि मिलेगी
- COVID 19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी
- ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में सहायता की जाएगी और PM केयर्स उस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान करेगा
- ऐसे बच्चों को आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) के तहत 18 वर्ष की आयु तक 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और प्रीमियम का भुगतान PM केयर्स द्वारा किया जाएगा

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

PM केयर्स फंड के बारे में:

- COVID-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए **'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (PM केयर्स फंड)'** के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है।
- प्रधानमंत्री, PM CARES कोष के पदेन अध्यक्ष और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, निधि के पदेन ट्रस्टी होते हैं।
- PM-केयर्स फंड में दान दी गई रकम पर इनकम टैक्स से 100 फीसदी छूट मिलेगी। यह राहत इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80G के तहत मिलेगी।
- PM-केयर्स फंड में दान भी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) व्यय के रूप में गिना जाएगा।
- PM केयर्स फंड को भी FCRA के तहत छूट मिली है और विदेशों से दान प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है।

मेकेदातु परियोजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल** द्वारा कावेरी नदी पर बांध के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल मेकेदातु में कथित उल्लंघनों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया है, के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है।

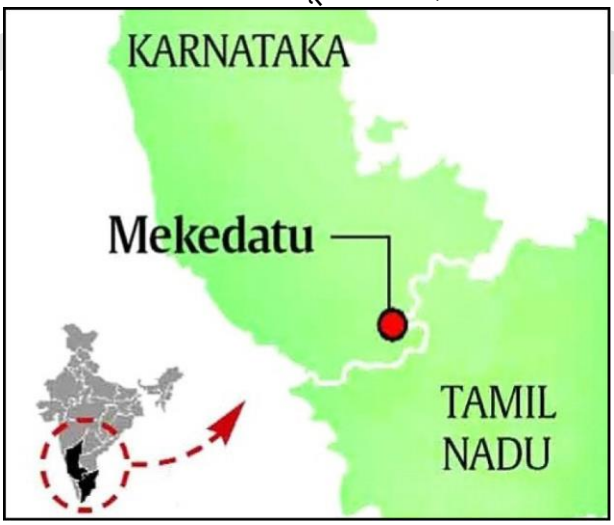

प्रमुख बिंदु

समिति के बारे में:

- **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल** (NGT) ने कर्नाटक में मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय के निर्माण में मानदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

मेकेदातु परियोजना

- यह एक बहुउद्देश्यीय (पीने और बिजली) परियोजना है, जिसमें रामनगर जिले के कनकपुरा के पास एक संतुलन जलाशय का निर्माण शामिल है।
- एक बार पूरी होने वाली परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु और पड़ोसी क्षेत्रों (4.75 TMC) को पीने का पानी सुनिश्चित करना है और 400 मेगावाट बिजली भी पैदा कर सकता है, और परियोजना की अनुमानित लागत 9,000 करोड़ रुपये है।
- यह पहली बार 2017 में कर्नाटक सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) से अनुमोदन महत्वपूर्ण है क्योंकि **कावेरी वन्यजीव अभयारण्य** का 63% वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा।

नोट: 2018 में, तमिलनाडु ने परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, भले ही कर्नाटक ने माना हो कि यह तमिलनाडु में पानी के प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगा।

तमिलनाडु द्वारा विरोध के कारण:

- तमिलनाडु ऊपरी तट पर प्रस्तावित किसी भी परियोजना का विरोध करता है जब तक कि इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।
- कर्नाटक को इस मामले में निचले तटवर्ती राज्य यानी तमिलनाडु की सहमति के बिना अंतर-राज्यीय नदी पर कोई जलाशय बनाने का कोई अधिकार नहीं है।
- यह परियोजना **कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT)** के अंतिम आदेश के खिलाफ है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई भी राज्य विशेष स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है या अन्य राज्यों को अंतर-राज्यीय नदियों के पानी से वंचित करने के अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है।

कावेरी नदी

- **कावेरी** एक भारतीय नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है।
- यह दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है और तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़ी है।

विवाद:

- चूंकि नदी कर्नाटक से निकलती है, केरल से आने वाली प्रमुख सहायक नदियों के साथ तमिलनाडु से होकर बहती है और पुडुचेरी से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए विवाद में 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

हाल के घटनाक्रम:

- सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला 2018 में आया जहां उसने कावेरी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया और CWDT द्वारा अंतिम रूप से जल-बंटवारे की व्यवस्था को बरकरार रखा और कर्नाटक से तमिलनाडु को पानी के आवंटन को भी कम कर दिया।
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कर्नाटक को 284.75 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (tmcft), तमिलनाडु को 404.25 tmcft, केरल को 30 tmcft और पुडुचेरी को 7 tmcft मिलेगा।
- इसने केंद्र को **कावेरी प्रबंधन योजना** को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने **'कावेरी जल प्रबंधन योजना'** जून 2018 में अधिसूचित की, जिसमें **'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' और 'कावेरी जल विनियमन समिति'** का गठन किया गया।

NCPCR ने ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल "बाल स्वराज (Covid देखभाल)" की शुरूआत की

चर्चा में क्यों?

- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग** (NCPCR) ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 109 के अंतर्गत एक निगरानी प्राधिकरण के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए और COVID-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल **"Bal Swaraj (COVID-Care Link)"** तैयार किया है।

प्रमुख बिंदु

"बाल स्वराज" के बारे में:

- आयोग का यह पोर्टल देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले **बच्चों के लिए ऑन लाइन ट्रैकिंग तथा डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग व्यवस्था** के उद्देश्य से बनाया गया है।
- आयोग ने इस पोर्टल के उपयोग को COVID-19 के दौरान माता-पिता या उनमें से किसी एक को खो देने वाले बच्चों की ट्रैकिंग के लिए बढ़ाया है और संबंधित अधिकारी/ विभाग द्वारा ऐसे बच्चों का डाटा अपलोड करने के लिए **"COVID-Care"** के नाम से लिंक प्रदान किया है।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

NCPCR के बारे में:

- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)** संसद के एक अधिनियम, **बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005** द्वारा स्थापित एक भारतीय वैधानिक निकाय है। आयोग भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। आयोग ने 5 मार्च 2007 को कार्य करना शुरू किया।

मध्य प्रदेश सरकार ने 'अंकुर' योजना की शुरूआत की

चर्चा में क्यों?

- मध्य प्रदेश सरकार ने मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए लोगों को पुरस्कृत करने के लिए 'अंकुर' योजना शुरू की।
- पौधरोपण की पहल करने वाले लोगों को उनकी भागीदारी के लिए **प्राणवायु पुरस्कार** दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

'अंकुर' योजना के बारे में:

- यह योजना कार्यक्रम में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेगी।
- जो लोग वृक्षारोपण अभियान में भाग लेना चाहते हैं, वे वायुदूत ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
- प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और 30 दिनों तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी।
- सत्यापन के बाद मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले से चयनित विजेताओं को प्राणवायु पुरस्कार प्रदान करेंगे।

एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021

चर्चा में क्यों?

- एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 31 वां संस्करण 24 से 31 मई 2021 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- भारत 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ 4वें स्थान पर रहा।
- **पदक तालिका**

रैंक	राष्ट्र	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1	कजाकिस्तान	8	6	2	16
2	उज्बेकिस्तान	7	6	5	18
3	मंगोलिया	3	0	5	8
4	भारत	2	5	8	15

नोट:

- भारत की **मैरी कॉम** ने 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता।
- एशियन चैंपियनशिप में मैरी कॉम के लिए यह दूसरा रजत है, जिन्होंने 2008 में रजत के अलावा पांच मौकों - 2003, 2005, 2010, 2012 और 2017 में खिताब जीता है।

सलमान रुश्दी की पुस्तक "लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ: एसेज 2003-2020"

चर्चा में क्यों?

- सलमान रुश्दी ने "लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ: एसेज 2003-2020" नामक एक नई किताब लिखी है।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

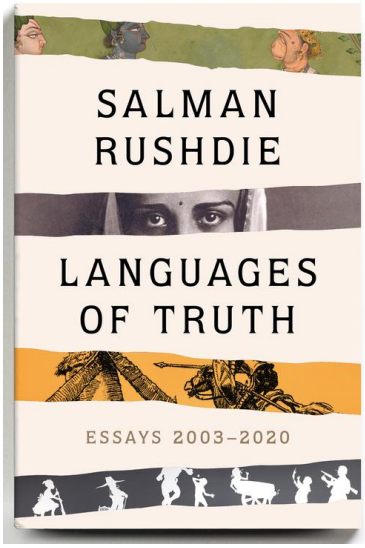

प्रमुख बिंदु

पुस्तक के बारे में:

- अपनी नई पुस्तक, "लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ: एसेज 2003-2020" में, रुश्दी एक रक्षात्मक कास्टिंग चाल करने का प्रयास करते हैं।
- उनका सुझाव है कि उनके काम को गलत समझा गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है क्योंकि साहित्यिक संस्कृति ब्रियो से भरे कल्पनाशील लेखन से "ऑटोफिक्शन" के विनम्र प्रसन्नता की ओर बदल गई है, जैसा कि ऐलेना फेरेंटे और कार्ल ओवे नोसगार्ड के काम का उदाहरण दिया गया है।

लेखक के बारे में:

- सलमान रुश्दी एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। उनके दूसरे उपन्यास, 'मिडनाइट्स चिल्ड्रन' (1981) ने 1981 में बुकर पुरस्कार जीता। उनके अधिकांश उपन्यास भारतीय उपमहाद्वीप पर आधारित है।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now